

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 18, शुक्रवार, शके 1946- फरवरी 07, 2025 Magha 18, Friday, Saka 1946- February 07, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

गृह (गुप- 10) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 6, 2025

एस.ओ. 63 .- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.14(6)विविध/गृह-10/2024 दिनांक 16 अगस्त, 2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:

राज्यपाल के आदेश से,

रवि शर्मा,

शासन सचिव, गृह

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

सं. एफ. 14(6)विविध/गृह-10/2024

जयपुर, दिनांक : अगस्त 16, 2024

अधिसूचना

यतः, निष्पक्ष और शीघ्र विचारण के लिए यह समीचीन है कि न्यायालयों द्वारा जारी आदेशिका सुरक्षित इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से और सुरक्षित इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग द्वारा जनित, जारी और निष्पादित की जायें;

यतः, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, अध्याय 6 के अधीन किसी गूढ़लेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य रूप में समनों को मान्यता प्रदान करती है;

यतः, संहिता की धारा 530 समनों और वारंट को जारी करने, तामील करने और निष्पादन करने के साथ-साथ समस्त कार्यवाहियों को इलैक्ट्रानिक ढंग में या इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग द्वारा करने का उपबंध करती है;

और यतः, राजस्थान राज्य में जिला न्यायपालिका और पुलिस के पास सुरक्षित, दक्ष और स्व-पर्याप्त पोर्टल अर्थात् केस इनफार्मेशन सिस्टम (सीआईएस), नेशनल सर्विस एंड ट्रेकिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसेज (एनएसटीईपी), क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) और इंटर-ओपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) हैं जो आपराधिक न्यायालयों द्वारा जारी आदेशिकाओं के जनन, पारेषण, तामील, अभिस्वीकृति और रिपोर्ट जनन को सुकर बनाने में सक्षम हैं; अब इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) की धारा 64 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक आदेशिकाएं (जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस)" से डाटा संग्रहण और अनुदेशों के निष्पादन के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला साफ्टवेयर/वेब पोर्टल अभिप्रेत है;

(ख) "केस इनफार्मेशन सिस्टम (सीआईएस)" से डाटा संग्रहण और अनुदेशों के निष्पादन के लिए न्यायालय द्वारा उपयोग किया जाने वाला साफ्टवेयर/वेब पोर्टल अभिप्रेत है;

(ग) "कोड" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(घ) "इलैक्ट्रॉनिक संसूचना" से टेलीफोन, मोबाइल फोन, या अन्य बेतार दूरसंचार डिवाइस, या कंप्यूटर, या श्रव्य-दृश्य प्लेयर या कैमरा को सम्मिलित करते हुए किसी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से या किसी अन्य ऐसे इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलैक्ट्रॉनिक प्रकार से, जो उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के द्वारा पारेषित या अंतरित (चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को) कोई लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) "इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से किसी उपयोगकर्ता या न्यायालय द्वारा किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसमें अंकीय चिह्नक सम्मिलित है। साथ ही, जब इलैक्ट्रॉनिक रूप में जनित आदेशिका या रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक के माध्यम से अधिप्रमाणित की जाती है, तो यह उस व्यक्ति के चिह्नक द्वारा अधिप्रमाणित की गयी समझी जायेगी जिसने इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक लगाया है;

(च) "सामान्य नियम" से सामान्य नियम (सिविल एवं फौजदारी), 2018 अभिप्रेत है;

(छ) "उच्च न्यायालय" से राजस्थान उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ज) "नेशनल सर्विस एंड ट्रेकिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसेज (एनएसटीईपी)" से न्यायालय आदेशिकाओं की तामील और प्रदाय के लिए उपयोग किया जाने वाला एंड्राइड ओएस एप अभिप्रेत है;

(झ) "आदेशिका" में समन, वारंट या ऐसे परिवर्तनों सहित जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अपेक्षित करें, संहिता या कोड की द्वितीय अनुसूची में दिये गये संहिता में वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए जारी कोई अन्य प्ररूप सम्मिलित है;

(ज) "ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल एड्रेस" से इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाला किसी व्यक्ति या संगठन का ई-मेल खाता अभिप्रेत है, जो ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या वेबसाइट या पोर्टल पर स्वीकृत, प्रयुक्त, या प्रदत्त दर्शित किया गया है;

(ट) "रजिस्टर" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप में उल्लिखित रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ठ) "संहिता" से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) अभिप्रेत है; और

(ड) "मुद्रा" से न्यायालय की मुद्रा की छवि अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ण) "समन" से कोड या संहिता के अध्याय 6 के अधीन जारी कोई समन अभिप्रेत है;

(त) "वारंट" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं जमानतीय वारंट और अजमानतीय वारंट।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) में समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. लागू होना.- (1) ये नियम कोड और संहिता की धारा 6 में उल्लिखित न्यायालयों के समस्त वर्गों को लागू होंगे। ये संहिता द्वारा और कोड द्वारा भी शासित होने वाले मामलों पर लागू होंगे।

(2) ये नियम न्यायालयों द्वारा आदेशिका के जारी करने, तामील करने और निष्पादन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये सामान्य नियमों के अतिरिक्त होंगे।

4. इलैक्ट्रानिक आदेशिका.- न्यायालय ऐसे परिवर्तनों सहित जैसा मामले की परिस्थितियां अपेक्षित करें, ऐसे रूप में जैसा कोड या, यथास्थिति, संहिता की द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित है, सीआईएस या एनएसटीईपी के माध्यम से इलैक्ट्रानिक ढंग में आदेशिका जनित और जारी कर सकेंगे।

5. आदेशिकाओं की भाषा- संहिता के अधीन इलैक्ट्रानिक संसूचना के रूप में जारी प्रत्येक आदेशिका सामान्यतः हिंदी में होगी, देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी और गूढलेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य रूप में होगी और इस पर न्यायालय की मुद्रा की छवि और अंकीय चिह्नक होंगे। यद्यपि, न्यायालय यदि समीचीन समझता है, तो आदेशिका को अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाने का निदेश दे सकेगा।

6. संपर्क सूचना संधारण करने के लिए पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी.- (1) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि सूचना देने वाले या पीड़ित या अभियुक्त या, यथास्थिति, साक्षियों द्वारा प्रयुक्त पते, ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पता, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित सत्यापित ब्यौरे गिरफ्तारी, अन्वेषण या जांच के दौरान अभिलिखित किये गये हैं और सीसीटीएनएस में प्रविष्ट किये गये हैं।

(2) ऐसी सूचना संहिता की धारा 64 की उप-धारा (1) की अनुपालना में पुलिस थाने में संधारित किये गये रजिस्टर में भी प्रविष्ट की जायेगी। यदि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी रजिस्टर में इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगा। ऐसी सूचना किसी अतिरिक्त सत्यापन के आधार पर या ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर संशोधित की जा सकेगी।

7. परिवादी का सूचना उपलब्ध करवाना.- जहां कोई मामला प्राइवेट परिवाद के आधार पर फाईल किया जाता है वहां परिवादी, परिवाद के साथ अभियुक्त और साक्षियों के पते, ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित ब्यौरे, यदि उसे ज्ञात हैं, फाईल करेगा। यदि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तो परिवादी इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगा।

8. आदेशिका जारी करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सूचना.- पते, ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित ब्यौरे इलैक्ट्रानिक रूप में पारेषित किये जायेंगे और सीआईएस में संधारित किये जायेंगे और आदेशिका जारी करने के लिए प्रयुक्त किये जा सकेंगे। ऐसी डिजीटल सूचना रजिस्टर का भाग होगी।

9. सूचना का प्रकट नहीं किया जाना.- (1) सूचना देने वाले, पीड़ित और साक्षियों के ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित सूचना कोड की धारा 207 और 208 या संहिता की धारा 230 और 231 के अधीन अभियुक्त को प्रतियां प्रदाय करते समय, उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी।

(2) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सूचना कोड की धारा 173 की उप-धारा (8) या संहिता की धारा 193 की उप-धारा (8) के अधीन प्रतियां तैयार करते समय प्रकट नहीं की जायें।

10. आदेशिकाओं का अधिप्रमाणीकरण.- (1) इलैक्ट्रानिक रूप से जारी प्रत्येक आदेशिका ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक चिह्नक अंतर्विष्ट करेगी जिससे कि न्यायालय का नाम या वह हैसियत जिसमें हस्ताक्षरकर्ता या उपयोगकर्ता कार्य करता है, स्पष्ट उल्लिखित हो।

(2) इलैक्ट्रानिक रूप में जनित समन पर न्यायालय के लिपिक या रीडर या, यथास्थिति, इस संबंध में लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक चिह्नक के साथ मुद्रा लगी होगी।

(3) इलैक्ट्रानिक रूप में गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के इलैक्ट्रानिक चिह्नक द्वारा जारी किया जायेगा और इस पर न्यायालय की मुद्रा की छवि लगी होगी।

11. आदेशिकाओं की उपधारणा.- जहां इलैक्ट्रानिक रूप में जनित आदेशिकाएं, गूढलेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य रूप में, सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से सीसीटीएस पर प्राप्त होती हैं, तो ये न्यायालय द्वारा जारी की गयी उपधारित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी आदेशिकाओं का कोई प्रिंटआउट वैसा ही प्रभाव रखेगा जैसे इसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए जारी किये गये मूल का है।

12. समन कैसे तामील किये जायेंगे.- (1) न्यायालय सीआईएस / एनएसटीईपी के माध्यम से इलैक्ट्रानिक ढंग में आदेशिका जारी कर सकेगा।

(2) न्यायालय, किसी पुलिस अधिकारी या इसे जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी या अन्य लोक सेवक को भी आदेशिका जारी करने का निदेश दे सकेगा।

(3) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधीनस्थ अधिकारी, न्यायालय द्वारा इलैक्ट्रानिक संसूचना के रूप में जारी किये गये समनों की प्राप्ति पर समन, समन किये गये व्यक्ति के ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर या मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अग्रेषित करेगा।

13. तामील की अभिस्वीकृति.- (1) जहां समन इलैक्ट्रानिक मेल के रूप में तामील किये जाते हैं, वहां इलैक्ट्रानिक मेल सेवा प्रदाता ऐसी रीति में प्रयुक्त किया जायेगा जिससे कि अभिस्वीकृति जनित हो और ऐसी अभिस्वीकृति तामील की रिपोर्ट का भाग होगी।

(2) जब कोई आदेशिका किसी व्यक्ति या संगठन को उसके ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते पर प्रेषित की जाती है, तो जब तक कि किसी भी कारण से इलैक्ट्रानिक मेल का प्रदाय बाधित या बाउंस बैक न हो, या मेल सर्वर से "रिटर्न टू सेंडर", "बाउंस बैक" या "एरर" संदेश प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, प्रदाय उस समय पर प्रभावी समझा जायेगा, जिस पर इलैक्ट्रानिक मेल, ई-मेल के सामान्य अनुक्रम में प्रदत्त की जाती है।

स्पष्टीकरण : ईमेल का सामान्य प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के अनुसार अवधारित किया जा सकेगा।

(3) जहां समन मैसेजिंग एप्लिकेशन को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से तामील किये जाते हैं, वहां अभिस्वीकृति तामील की रिपोर्ट का भाग होगी और रिपोर्ट में मोबाइल नम्बर, मैसेजिंग एप्लिकेशन और संसूचना के प्रदाय को दर्शित करने वाले एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट/फोटो को सम्मिलित करते हुए ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(4) ऐसा प्रदाय समन/आदेशिकाओं की सम्यक् तामील समझा जायेगा और तामील की रिपोर्ट के साथ ऐसे समनों/आदेशिकाओं की प्रति समनों/आदेशिकाओं की तामील के सबूत के रूप में अभिलेख में रखी जायेगी।
स्पष्टीकरण : इस नियम के अधीन अभिस्वीकृति में निम्नलिखित द्वारा दी गयी कोई अभिस्वीकृति सम्मिलित है, -

(i) प्रेषिती द्वारा कोई संसूचना, स्वचालित या अन्यथा; या

(ii) प्रेषिती का कोई आचरण जो प्रवर्तक को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त हो कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त हो गया है।

(5) जहां कोई आदेशिका इलैक्ट्रानिक ढंग से अन्यथा तामील या निष्पादित की जाती है, वहां तामील या आदेशिका निष्पादित करते समय पुलिस अधिकारी फोटो लेगा और प्राप्तकर्ता की अभिस्वीकृति लेगा, जो तामील की रिपोर्ट का भाग होगी।

14. समन किये गये व्यक्ति की सूचना की कमी.- यदि, समन किये गये व्यक्ति से संबंधित ईमेल पते, फोन नम्बर या मैसेजिंग एप्लिकेशन की सत्यापित सूचना उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी इस संबंध में प्रविष्टि करेगा और इलैक्ट्रानिक ढंग में जारी किये गये समनों का दो प्रतियों में प्रिंटआउट लेने के पश्चात्, कोड या संहिता के अध्याय 6 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार इसकी तामील करवायेगा।

15. तामील नहीं किये गये समन.- जब समन इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य ढंग द्वारा तामील नहीं किये जाते हैं या प्रदाय किसी अन्य कारण से बाधित और बाउंस बैक हो जाता है, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी मोबाइल नम्बर, मैसेजिंग एप्लिकेशन, एप्लिकेशन के स्क्रीन शॉट/फोटो सम्मिलित करते हुए समस्त अंतर्विष्ट करके उस संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा और समनों की तामील के लिए नियम 14 के अनुसार अग्रसर होगा।

16. वारंट कैसे तामील किये जायें.- यदि वारंट या कोई अन्य आदेशिका इलैक्ट्रानिक ढंग में जारी किये जाते हैं, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी वारंट या

आदेशिका का प्रिंटआउट लेगा और कोड या संहिता और उस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार इसका निष्पादन करेगा।

17. आदेशिकाओं की लंबित तामील के लिए न्यायालय को तामील रिपोर्ट.- आदेशिका की बकाया तामील या तामील नहीं होने पर, संबंधित पुलिस थाने का तामील अधिकारी जमानतपत्रों, फोटो, स्क्रीनशॉट्स, अभिस्वीकृति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए सुसंगत दस्तावेजों के साथ, सीसीटीएनएस/एनएसटीईपी के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में संबंधित न्यायालय को तामील रिपोर्ट पारेषित करेगा, और ऐसी तामील/निष्पादन रिपोर्ट भौतिक रूप में भी अग्रेषित करेगा।

18. तामील रिपोर्ट पर विचार किया जाना.- न्यायालय, नियम 17 के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकेगा। ऐसी रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्ट का प्रिंटआउट आदेशिका की तामील/निष्पादन के समाधान के प्रयोजन के लिए मूल के रूप में समझा जायेगा।

19. कुछ मामलों में पहचान प्रकट नहीं किया जाना.- जहां कोई आदेशिका भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 से 376ड या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 से 71 के अधीन अपराधों या महिला अथवा बालकों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में जारी की जाती है, वहां पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि तामील या निष्पादन के क्रम में किसी भी रीति में पीड़ित की पहचान प्रकट नहीं हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में भौतिक रूप में रिपोर्ट, न्यायालय को मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी।

20. कोड के अधीन लंबित मामलों में आदेशिकाएं.- इन नियमों में कुछ भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा शासित होने वाले लंबित मामलों में, इन नियमों के अधीन आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के जनन और निदेश देने की न्यायालयों की शक्तियों को सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

प्ररूप

बीएनएसएस, 2023 की धारा 64(1) के अधीन रजिस्टर

क्र. सं.	प्र.सू.रि. सं. पुलिस थाना	न्यायालय का नाम और स्थान	मामला शीर्षक	सीएनआर सख्याक	न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने की तारीख और समन किये गये व्यक्ति या जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, का नाम और पता	आदेशिका का प्रकार	उपस्थिति तारीख	अपराध अधीन	नातेदार का नाम, यदि समन तामील हुआ है।	तामील आदेशिका प्रास्थिति	टीका-टिप्पणियां
1											
2											
3											

[पत्रावली सं.प. 14 (6) विविध/गृह-10/2024]

राज्यपाल के आदेश से,

रवि शर्मा,
शासन सचिव।